International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Volume 01, No. 03, July - September, 2019, pp.245-252

वैश्वीकरण के दौर में मेक इन इण्डिया योजना का प्रभाव

उषा शर्मा*

प्रस्तावना

21वीं शताब्दी के प्रथम दशक की समाप्ति तक भूमंडलीकरण का कुरूप चेहरा अच्छी तरह साफ हो गया है। इसका एक पहलू वह है जिसमें विश्वभर में परिष्कृत टैक्नालॉजी पर आधारित औद्योगिकरण तो तेजी से बढ़ा है पर इसके साथ–साथ दुनियाभर में कृषि का ह्रास भी उसी गति से हुआ है। इसका सबसे दुःखदायक परिणाम यह है कि विकासशील कहे जाने वाले अर्थात् गरीब देशों में, जिनकी बहुतायत एशिया और अफ्रीका में है, देहाती क्षेत्रों में रहने वालों की जिंदगी दूभर हो गई है। खेती की जमीनें बड़े पैमाने में औद्योगिक संयंत्रों ने घेर ली हैं और खनिज प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण कई स्थानों पर नाजुक पारिस्थितिकी बिगड़ गई है। बडे पैमाने पर अपनी पारंपरिक जीविका के साधन गंवा देने के बाद लोग विस्थापित हुए हैं और आंतरिक शरणार्थी बनने को मजबूर हुए हैं। कई बार जिंदा रहने के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करना पड़ा है और बाहरी अवांछित मेहमान होने के कारण नस्लवादी हिंसा का शिकार भी बनना पड़ा है।

भूमंडलीकरण का एक बुनियादी तर्क यह था कि जैसे–जैसे भूमंडलीकरण की प्रक्रिया तेज होगी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बाजार के तर्क के अनुसार मांग और पूंजी के दबावों से अनुकूलित होकर आत्मनिर्भर होती जाएगी। त्वरित आर्थिक विकास का लाभ धीरे–धीरे सभी जगह पहुंचेगा और सबसे वंचित और निर्बल व्यक्ति की जिंदगी में भी सुधार होगा। आज इस प्रक्रिया के दो दशक से भी अधिक समय तक गतिशील रहने के पश्चात् भी यह भविष्यवाणी सच सिद्ध नहीं हुई है। वास्तविकता तो यह है कि जो कुछ भी संभव हुआ है वह इसके विपरीत ही हुआ है।

जो प्राकृतिक संसाधन संपन्न भू–भाग थे पर राज्य के रूप में ताकतवर नहीं थे व भू–भाग अपना स्वामित्व लगभग पूरी तरह गंवा चुके हैं। तेल और गैस हो, सोना अन्य खनिज अथवा जवाहारात सभी के बारे में यह देख जा सकता है। उदाहरणार्थ, इराक जैसे देश में सत्ता परिवर्तन के नाम पर बर्बर सैनिक हस्तक्षेप द्वारा अमरीका जैसी महाशक्ति ने अपना प्रभुत्व इस तरह स्थापित कर लिया है जिसे निकट भविष्य में चुनौती देने के बात कोई दूसरी शक्ति सोच भी नहीं सकती या फिर अबाध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम पर साधन संपन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने ऐसे लाभदायक सौदे–समझौते तानाशाहों या भ्रष्ट सरकारों के साथ कर लिए हैं, जिनके बाद इन राज्यों की संप्रभुता नाममात्र की ही शेष रही है और अपने संसाधनों पर उनके अधिकारों की दावेदारी केवल नाममात्र ही शेष रही है।

वैश्वीकरण और भारत

एक अमेरिकी विद्वान लेस्टर सी. थूरो ने अपनी पुस्तक 'दि फ्यूचर ऑफ कैपिटलिज्म' में लिखा है कि 'विश्व व्यापार व्यवस्था के नियम–कायदे सदैव वर्चस्वशील अर्थव्यवस्थाओं ने निश्चित किए हैं और लागू कराए हैं। 19वीं सदी में ग्रेट ब्रिटेन ने यह भूमिका निभाई और 20वीं सदी में संयुक्त राज्य अमेरिका ने। परंतु 21वीं सदी में आर्थिक प्रबंधन के नियम–कायदो की रूपरेखा बनाने, संगठित करने और उन्हें लागू कराने वाली कोई

* शोधार्थी, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान।

भी वर्चस्वपूर्ण शक्ति नहीं रहेगी। अमेरिका के प्रभाव में संचालित एक–ध्रुवीय व्यवस्था के दिन लद चुके हैं और एक बहुध्रुवीय संसार उभर कर विश्व रंचमंच पर आ चुका है।' 9/15 के बाद जब विश्व बैंक के कुछ रणनीतिकारों ने 'डी–कपुलिंग' (विच्छेदीकरण) की अवधारणा प्रस्तुत की तो 'थूरो' की बात सच होती दिखने लगी। इसके बाद से इस बात का चलन बौद्धिक जगत में चल पड़ा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मंदी में चले जाने के बाद भारत और चीन की अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। जबकि सच यह है कि नैसडैक और डाउजोंस में होने वाले परिवर्तनों से ब्राजील, चीन और भारत के शेयर बाजारों को छींके आने लगती हैं या फेडरल रिजर्व द्वारा अपनी नीतियों में परिवर्तन लाते ही दुनिया भर की मौद्रिक बाजारों में हड़कंप मच जाता है।

सोवियत संघ के पतन के साथ ही स्वच्छंद और निरंकुश पूंजीवाद का युग आरंभ हुआ। इतिहास के अंत की घोषणा के साथ ही निरंकुश पूंजीवाद ने दुनियाँ भर के लिए मार्ग दर्शक सिद्धांत निश्चित कर दिये। अब भारत और उस जैसी बहुत सी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह तय करना अनिवार्य हो गया था कि वे अर्थव्यवस्था के पश्चिमी संस्करण को स्वीकार करेंगे या फिर अभी भी परम्परावादी ही बने रहेंगे। अततः तीसरी दुनिया के देशों के तीव्र विकास की उत्कट इच्छा और उसके लिए अधिक से अधिक विदेशी निवेश की आवश्यकता ने बड़ी सहजता से पूंजीवाद के नये पश्चिमी संस्करण का चुनाव कर लिया। भारत ने भी 1990 के दशक में अपनी अर्थनीति बदलते हुए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समक्ष समर्पण कर दिया। लेकिन सतत् विकास के अपने पारम्परिक मॉडल (आर्थिक नियोजन) को बनाए रखा। इस दौरान एक परिवर्तन अवश्य आया और वह था आर्थिक संवृद्धि में सभी समस्याओं का निदान ढूंढना।

1990 के दशक के प्रारंभ होते–होते भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लग चुका था जिससे उबरने के लिए भारत के नीतिकारों को उदार अर्थव्यवस्था को अपनाने का संकल्प लेना था। इसके बाद भारत ने 'वाशिंगटन आमराय' द्वारा निर्मित ढांचागत समायोजन कार्यक्रम (स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम; सैप) के तहत विदेशी पूंजी मुक्त बाजार, निजीकरण तथा सरकारी आर्थिक भूमिका में भारी कटौती की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद से भारत ने आर्थिक विकास के छद्म रूप संवृद्धि (ग्रोथ ना कि डेवलपमेंट) के क्षेत्र में तरक्की के लिए मार्ग तलाशना शुरू कर दिया। अगर आंकड़ों को देखें तो इस तथाकथित मंदी के आने के पहले तक भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार 300 अरब डॉलर के आस–पास था, संवेदी सूचकांक कुलांचें भर रहा था, विकास दर नौ प्रतिशत के आस–पास थी, पर्चेजिंग पॉवर पैरिटी (पीपीपी) के सुरक्षित ढाल के पीछे भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और भारत के 56 अरबपति फोर्ब्स में अपना नाम दर्ज करा चुके थे। इसके बाद घोषणा की जाने लगी कि भारत 2025 में एक विकसित राष्ट्र होगा।

आशय यह कि जो भी आशावादी घोषणाएं हो रही है वे भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर (ग्रोथ रेट) और सेवा क्षेत्र की बढ़त को देखते हुए की जा रही हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि ग्रोथ किसी अर्थव्यवस्था की समृद्धता (साउन्डनेश) को पहचानने का आदर्श तरीका नहीं और सेवा तो सही अर्थों में अर्थव्यवस्था में एक छद्म नाम है। हां इस दौर में भारत में अरबपतियों की संख्या अवश्य बहुत अधिक हुई है। इसलिए फोर्ब्स को देखकर समृद्धता का निष्कर्ष निकाल लिया जाता है और वास्तविक पक्ष को गौण कर दिया जाता है। भारतीय विकास का एक पक्ष यह भी है कि भारत को 'राइट टू फूड एक्ट' की आवश्यकता पड़ रही है। वास्तविकता यह है कि भारत में भुखमरी और कुपोषण का संकट दक्षिण अफ्रीका के देशों की तुलना में कहीं अधिक है।

भारत का हर दूसरा बच्चा कुपोषित है ओर यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर दिन 5000 बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। भारत की हर दूसरी महिला एनीमिया से पीड़ित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुषंगी संस्था खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के वर्तमान प्रतिवेदन के अनुसार भारत में 23 करोड़ से अधिक लोग भूख का शिकार हैं। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों की हालत अफ्रीका के इथियोपिया, कांगो और चाड जैसी है। भले ही भारत ने चीन से ज्यादा अरबपतियों को जन्म दिया हो लेकिन वैश्विक भूख सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) के मामले में चीन के मुकाबले भारत की स्थिति खराब है। हालांकि सभी वैश्विक सूचकांकों में कुछ न कुछ त्रुटियां होती है और यह आवश्यक भी नहीं होता कि ये सूचकांक

वास्तविकता को दर्शाते हों। लेकिन भारत की उस अमीरी, जिसका उल्लेख सभी पूंजीवादी संस्थाओं से लेकर सरकार तक करती रहती है, का यह सबसे बदरंग पहलू है। भुखमरी के मामले में भारत की गिनती उन 25 देशों के समूह के साथ होती है जिसमें सब–सहारा अफ्रीका के देश भी सम्मिलित है, जहां भूख का स्तर खतरनाक स्थिति में है। सूचकांक में भारत 67वें, नेपाल 56वें, पाकिस्तान 52वें और श्रीलंका 39वें पायदान पर है। दक्षिण एशिया में केवल बांग्लादेश ही भारत से ऊपर (68वें स्थान पर) है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएफपीआरआई) ने दो वैश्विक गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) वेल्थहंगरहिल्फ व कंसर्न कर्ल्डवाइड के सहयोग से यह सूचकांक तैयार किया है। यह भूख के तीन महत्वपूर्ण संकेतकों पर आधारित है और हर संकेतक का समान भार (वेटेज) है, अर्थात्–अल्पपोषित आबादी का प्रतिशत, पांच वर्ष से कम उम्र के सामान्य से कम वजन वाले बच्चों का अनुपात और शिशु मृत्यु दर। यहाँ सामान्य से कम वजन वाले 43.5 प्रतिशत बच्चे हैं, जो भारत के सूचकांक को नीचे ले जाते हैं। यह दुःखद है कि भारत सामान्य से कम वजन वाले दुनिया के कुल बच्चों में से 42 प्रतिशत का घर है और 31 प्रतिशत बच्चों का विकास अवरूद्ध है।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमृत्य सेन का मानना है कि गरीबी और भुखमरी को एक–दूसरे से जोड़कर देखना चाहिए। वे यह भी मानते हैं कि संकट यह नहीं है कि देश में अनाज का संकट है या उत्पादन अचानक न्यूनतम स्तर पर आ गया है। असली संकट यह है कि लोगों के पास पैसा नहीं है कि वे अनाज खरीद सकें। गरीबी और भुखमरी का आपस में जुड़ा हुआ अर्थशास्त्र है अर्थात् गरीबी भुखमरी और कुपोषण को बढ़ाती है, ये दोनों शारीरिक व मानसिक शक्तिहीनता को बढ़ाते हैं जिससे श्रम की सकल मात्रा व क्षमता दोनों ही घट जाती है। यह स्थिति उत्पादन को घटाती है और न्यून उत्पादन गरीबी को और बढ़ा देता है। इस प्रकार से गरीबी और भुखमरी का कुचक्र आरंभ हो जाता। असंगठित उद्योगों पर गठित राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट को देखें तो ज्ञात होगा कि 84.8 करोड़ आबादी प्रतिदिन 20 रुपये से भी कम पर गुजारा करती है। वास्वत में अल्पपोषण की समस्या खाद्यान्न की कमी की वजह से नहीं है बल्कि इसलिए है क्योंकि उपलब्ध स्टॉक जरूरतमंदों तक या तो पहुंच नहीं पा रहे हैं या फिर इसे उन कीमतों पर नहीं बेचा जा रहा है जिसे खरीदने की वे क्षमता रखते हैं। चिकित्सकीय साक्ष्य बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चरण तब आता है जब जीवन के पहले 100 दिन में पोषण अनिवार्य होता है अर्थात् गर्भधारण और बच्चे के जन्म के मध्य। दो साल की उम्र के बाद अल्पपोषण का बुरा प्रभाव स्थायी होता है। इसमें संशय नहीं कि पिछले दशक में भूख को समाप्त करने के लिए भारत ने बहुत प्रगति की है लेकिन यह देखते हुए कि कुछ गरीब देशों ने उससे बेहतर काम किया है, भारत की प्रगति संतोषजनक नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बीते दशक में प्रतिव्यक्ति आय में उत्साहजनक वृद्धि हुई है लेकिन इसने गरीबी में कमी लाने या भूख पर बहुत ज्यादा असर नहीं डाला। इसका एक पक्ष बाजारवादी है और दूसरा पक्ष सरकारी है जो प्रबंधन दक्षता की कमी को व्यक्त करता है।

इन परिणामों को देखते हुए वैश्वीकरण को किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए, विकास के वैश्वीकरण से या गरीबी के वैश्वीकरण से क्योंकि भारत एक साथ दोनों से जुड़ा हुआ है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भूमंडलीकरण का प्रभाव–परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। संपूर्ण विश्व के लिए भूमंडलीकरण की मंशा व्यापारिक उदारता, निजीकरण और सांस्कृतिक निकटता पर आधारित है जिसका शिकार भारत भी होता आया है। आज भारत वैश्विक रंगमंच पर अपनी भूमिका निभाने को आतुर है तो इसके पीछे भूमंडलीकरण की ताकत भी सम्मिलित है। बेशक भारत के लिए भूमंडलीकरण पूर्णतया सकारात्मक ही नहीं रहा है फिर भी इसे सिरे से खारिज करना संभव नहीं। यदि प्रतिक्रियावादी चश्मे से भारत पर भूमंडलीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन करेंगे तो यह नकारात्मक ही दिखाई देगा। किन्तु यदि निरपेक्ष दृष्टि रखें तो यह भारत के विकास में सहायक भी दिखता है। केवल हमें विकास के लाभ को कतिपय लोगों के स्थान पर सबके द्वार तक पहुंचाना होगा। आज अगर आईटी सेक्टर में हमारी धाक है और हम अमेरिका जैसे विकसित देश के छात्रों को नौकरी अमेरिका जाकर भी छीन लेते हैं तो क्या भूमंडलीकरण को नकारा जा सकता है? शायद नहीं। जहाँ तक संस्कृति की बात है तो मज़बूत संस्कृतियाँ कभी मिटा नहीं करतीं बल्कि उनका रूपांतरण होता है, और संस्कृति की खूबसूरती उसकी विविधता में है, न कि एकरूपता में। इसलिए भारत

सांस्कृतिक समन्वय का जीता–जागता उदाहरण है। फिर भी यदि सहमति गढ़कर संस्कृति को भ्रष्ट करने या पश्चिमी सांस्कृतिक वर्चस्व थोपने का प्रयास हो तो उससे अवश्य बचने की आवश्यकता है। ग्लोबलाइजेशन का स्वागत हमें वहीं तक करना चाहिए जहाँ तक वह विचार, सूचना विज्ञान के क्षेत्र में हो। क्षमा, करुणा, दया, अहिंसा, संवेदना मैत्री और शांति के पक्ष में हो। वह कॉम्पेटिटिव न होकर पूरक (कॉम्पलीमेंट्री) हो। वरना हम स्वर्ग का सपना देखते–देखते कहीं नरक में न पहुंच जाएँ।

भारत में सुधारों की प्रक्रिया को तीन अन्य प्रक्रियाओं अर्थात् उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (जिसे एल.पी.जी. कहा जाता है) की प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण किया जाना निश्चित है। ये तीन प्रक्रियाएँ भारत द्वारा प्रवृत सुधार प्रक्रिया के लक्षणों को वर्जित करती हैं। स्पष्ट रूप से उदारीकरण सुधार की दिशा, निजीकरण सुधार के मार्ग और वैश्वीकरण सुधार के अंतिम लक्ष्य को दर्शाते हैं। विगत कई वर्षों में संपूर्ण दुनिया वैश्वीकरण प्रक्रिया की त्रुटियों पर बढ़ी बहस की साक्षी रही है। न केवल विशेषज्ञों के मध्य बल्कि कई राष्ट्रों की भी सामान्य धारणा वैश्वीकरण की विरोधी होती गई है। विश्व व्यापार संगठन के लेकर होने वाली वार्ता लगभग रूक गई है। वर्ष 2016 का उत्तरार्द्ध पूरे विश्व की समस्त महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में संरक्षणवादी भावना दिखाई दी है। भारत ने अपने बचाव में एक मध्य का रास्ता निकालने का प्रयत्न किया है। मेक इन इण्डिया पहल ही वह मार्ग है जिस पर चलकर भारत अपना विकास निरंतर जारी रख सकता है। ''मेक इन इण्डिया'' कार्यक्रम के अनुसार जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनमें प्रमुख है–निवेश को महत्व, नवपरिवर्तन को प्रोत्साहन, कौशल विकास में वृद्धि, प्रज्ञात्मक संपत्ति की सुरक्षा, सर्वश्रेष्ठ आधारभूत संरचना का निर्माण करना। उक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जो सपना संजोया गया है वह है निवेश को सरल व सुगम बनाना, कौशल विकास को प्रोत्साहन देना, रोजगार के अवसर पैदा करना, विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना का निर्माण करना। संपोषणीय और नये उत्पादों को भारत में निर्मित करना। भारत को एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकसित करना तथा स्मार्ट शहरों का विकास करना।

मेक इन इण्डिया योजना का प्रभाव

इस पहलू के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव देखे गये हैं। ढांचागत विकास देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है। गरीबी का निवारण तथा निवेश को आकर्षित कर रही है। भारतीय सामान की अच्छी कीमत और व्यापारिक घाटे को निश्चित करेगी। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के स्तर को विश्व में ऊंचा उठायेगी। निवेशक भारत की ओर केवल बाजार के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखेंगे। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय के मध्य पारस्परिक क्रिया मजबूत होगी और घरेलू कंपनियाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बदल जायेगी। पड़ोसी देश चीन ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर इसी आधार पर बनाया है। भारत भी चीन की तरह लोकतंत्र जनसांख्यकीय का लाभ उठाते हुए अपने आपको एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने की महत्वाकांक्षा रखता है और अपने विदेशी निवेश को बढ़ावा देकर एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बन सकता है। इस अभियान से आकर्षित कई देश जिनमें जापाना, अमेरिका तथा चीन ने निवेश करके सहयोग प्रदान किया है।

पर्यटन एवं विदेशी मेहमानों के आगमन से भारत के आर्थिक विकास को संबल मिलेगा। आशा है भारत की जीडीपी में 7.5 प्रतिशत वृद्धि हो सकेगी तथा विदेशी सैलानी भारतीय विरासतों को देखकर गौरवान्वित होंगे। इससे इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आई.टी. क्षेत्र में भी जीडीपी 9.3 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। विगत पांच वर्षों में 13.5 प्रतिशत जीडीपी दर्ज की गई है तथा 1,50,000 लोगों को रोजगार मिला है। सूचना और औद्योगिक क्षेत्र में और अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे तथा लोगों को इस क्षेत्र में लाभ अधिक मिलेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस अभियान का प्रभाव देखा गया है। इस क्षेत्र में उत्पादन 25 प्रतिशत तक बढ़ाने का उद्देश्य निर्धारित किया है। मेक इन इण्डिया की पहल से सन् 2015–16 में जीडीपी 7.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

आई.टी. सेक्टर में इस योजना के प्रभाव से रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। निर्माण कार्य (कन्सट्रकशन) सेक्टर में सन् 2009–10 में देश की जीडीपी को इसका योगदान 62–63 प्रतिशत था। सरकार ने

यह निश्चित किया है कि इसके सहयोग को बढ़ाकर 70 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक वर्ष 2030 तक किया गया है। वैसे रीयल–स्टेट भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र के जिसमें सबसे अधिक लोग कार्य कर रहे है। सरकार ने करीब एक ट्रीलियन धनराशि सन् 2017 तक निवेश की है। इसमें निजी क्षेत्र ने 40 प्रतिशत निवेश किया है। 45 प्रतिशत राशि निर्माण कार्य पर खर्च की है और 20 प्रतिशत राशि अन्य कार्यों पर अग्रिम रूप से व्यय की गई है।

ऑटोमोबाइल सेक्टर भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। सन् 2026 तक यह दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र होगा। दुपहिया वाहनों का उत्पादन 8.5 मिलियन यूनिट प्रतिवर्ष होगा। कार–बाजार 6 मिलियन यूनिट सन् 2020 तक उपजेगा। इस उद्योग का देश की जीडीपी में 45 प्रतिशत योगदान है। लगभग 19 मिलियन लोग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। भारत दुनियाँ का 7वां बड़ा दुपहिया वाहन उत्पादक देश है। लगभग 24 मिलियन वाहन वार्षिक बनाये जा रहे हैं। कुल उत्पादन का 3.64 मिलियन वाहन निर्यात किये जा रहे हैं। सरकार चाहती है इस सेक्टर का स्थान 7 के स्थान पर तीसरा रखना चाहिए और सन् 2016–17 में यह उपलब्धि प्राप्त भी हुई है। वर्तमान में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसने दुपहिया वाहन निर्मित किये हैं। 'मेक इन इण्डिया' पहल मुख्यतः रोजगार के अवसर ही उपलब्ध नहीं करवा रही है बल्कि भारत की जीडीपी में वृद्धि कर रही है। इसलिए यह भारत के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रही है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 101 देशों में गरीबी दर प्रतिवेदन जारी किया है। भारत ने 2006–2016 के मध्य 10 विकासशील देशों के समूह में सबसे तेज गति से गरीबी का उन्मूलन किया है। इन 10 वर्षों में देश के 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आये है। यू.एन.डी.पी. की मल्टीडाइमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 33.1 प्रतिशत (64 करोड़) से घटकर 27.9 प्रतिशत (36.9 करोड़) रहे गये हैं। रिपोर्ट में भारत के साथ बांग्लादेश, कंबोडिया, हैनी, पेरु, कांगो, इथोपिया, नाइजीरिया, पाह, वियतनाम को भी सम्मिलित किया गया है। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में स्वीकारा है कि विगत 8 वर्षों में बेरोजगारी की दर बढ़कर दोगुनी हो गई है। नवंबर, 2016 में नोटबंदी के पश्चात् से विगत दो वर्षों में 50 लाख लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। इनमें अधिकतर बेरोजगार उच्च शिक्षा प्राप्त युवा है। प्रतिवेदन के अनुसार 2018 में बेरोजगारी की दर बढ़कर 6 प्रतिशत पहुंच गई है। जो वर्ष 2000 से 2011 में बेरोजगारी की दर से दोगुना है। लेकिन नोटबंदी का बेरोजगारी में वृद्धि से संबंध स्थापित नहीं किया है। इन्फोसिस कंपनी के सीइओ व एम.डी. सलिल परेख का मानना है कि कंपनी ने इस वित्त वर्ष के प्रारंभ में मजबूती दिखाई है। कंपनी जून 2019 के तिमाही में आय 14 प्रतिशत से बढ़कर 21,803 करोड़ रही। पिछले साल भी समान अवधि में यह 19.128 करोड़ थी। कंपनी ने 10 करोड़ से अधिक के दो ग्राहक और जोड़े हैं। कुलमिलाकर इनकी संख्या 25 हो गई। कंपनी की वैश्विक कारोबार में भागीदारी निम्नानुसार थी–

उत्तरी अमेरिका	61.6%
यूरोप	23.6%
शेष दुनियाँ	12.5%
भारत	2.3%
कुल	**100**%

आईटीएल (इण्डियन ट्रेक्टर लिमिटेड कम्पनी) और जापानी कम्पनी धनमार के मध्य साझेदारी हुई है। सोलिस ट्रेक्टर के निर्माण से भारतीय कंपनी ने भारी लाभ अर्जित किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले चैम्पियन क्षेत्रों को पहचान की गई है। जिसमें विश्वस्तर पर चैम्पियन बनने की क्षमता है। योजना के तहत रोजगार बढ़ेंगे जिससे देश में बेरोजगारी की समस्या दूर होगी साथ ही इन क्षेत्रों में कौशल विकास होगा। जिससे देश–विदेश में सभी बड़े निवेशकों का ध्यान हमारी और केंद्रित हेागा।

'मेक इन इंडिया' अभियान की मदद से बहुत से बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल रहा है इसी के परिणाम स्वरूप देश का विकास भी हो रहा है। इस अभियान की सहायता से भारत को अन्य विकसित देशों में सूचि में शीघ्र ही सम्मिलित कर सकेंगें। अगर विदेशी की कंपनियां हमारे देश में शाखाएं खोलेंगी तो भारत के साथ–साथ उन्हें भी लाभ होगा और देश के लोगों को भी कम दाम में उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे और साथ में

लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार और विकास होगा। 'मेक इन इंडिया' अभियान शुरू हुआ तब से भारत में शिघ्रता से कई निवेशकों ने विनिर्माण, वस्त्र, ऑटोमोबाइल, उत्पादन, खुदरा, रसायन, आईटी, बंदरगाह, फार्मास्यूटिकल, पर्यटन, आदि ने रेल्वे के क्षेत्र में निवेश किया है जो भारत के लिए एक बहुत ही प्रसन्नता की बात है।

योजना के शुभारंभ के दिन सभी अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय कंपनियों को इस अभियान का साथ देने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस अभियान में भारत में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में निवेश के क्षेत्र में एक क्रांति उत्पन्न कर दी है। इसमें रोज कोई–ना–कोई बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी भारत में निवेश कर रही है और अपनी शाखाओं को भारत में स्थापित कर रही है जो आने वाले वर्षों में लोगों के लिए रोजगार का एक अच्छा माध्यम होगा। 'मेक इन इंडिया' अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत में नई टेक्नॉलाजी के विकास और भारत में ही बनाए जाने वाले उत्पादों को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य सिद्धांत है कि विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रेरणा मिले तथा भारत में ही उत्पादों का निर्माण हेतु प्रोत्साहन दिया जाए। ना केवल विदेशी उत्पादों बल्कि येाजना के तहत भारती कंपनियों के उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में आजतक अशिक्षा, बेरोजगारी महिलाओं की संख्या में गिरावट, भ्रष्टाचार, गरीबी और स्वास्थ्य सेवाओं की अपर्याप्ता है। मेक इन इंडिया अभियान इन सभी कमियों के निराकरण की एक बहुत ही अच्छी पहल है।

मेक इन इंडिया अभियान के अनुसार भारत में 100 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और सस्ते आवास लोगों को मिलने की आशा है। अधिक से अधिक वस्तुऐं भारत में उत्पादित हों जिससे वस्तु की कीमत कम रहेगी और बाहर निर्यात करने पर देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। देश में रेाजगार बढ़ेगा, गरीबी कम होगी। उच्च गुणवत्ता का समान कम कीमत पर मिलेगा। विदेशी के निवेशक हमारे यहाँ निवेश करेगे। जिससे देश में बाहर से पैसा आएगा साथ ही देश का नाम दुनियाँ में रोशन होगा। देश के नौजवानों को अपना कौशल प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। देश के युवा रोजगार हेतु विदेशों में पलायन नहीं करेंगे। सितम्बर, 2014 में जब से इस योजना की शुरूआत हुई है तब से नवम्बर 2015 तक भारत सरकार को दुनियाँ भर की इलेक्ट्रानिक्स कंपनियों ने प्रस्ताव भेजे हैं जो भारत में काम करने के इच्छुक हैं। जनवरी 2015 को स्पाइस मोबाईल कंपनी के मालिक ने उत्तर प्रदेश के साथ डील करके वहाँ पर अपने मोबाइल फोन की कंपनी स्थापित की है। जनवरी 2015 में ही सैमसंग मोबाइल कंपनी के सीईओ ह्यून चिल होंग एमएसएमई के मंत्री कलराज मिश्रा से मिले थे। उन्होनें साथ में काम करने की इच्छा प्रकट की थी और नोएडा में इसके प्लांट की बात भी कही थी। फरवरी 2015 में हिताची ने भी भारत में निवेश की बात कही और कहा वे चेन्नई में अपना स्टार्टअप लगा सकते हैं।

फरवरी, 2015 में हुवाई ने बैंकलुरू में अपना रिसर्च व डेवलपमेंट कैंपस खोला। इसके साथ ही उन्होनें टेलीकॉम हार्डवेयर प्लांट चेन्नई में बनाने की बात कही जिसे चेन्नई सरकार ने मान्यता दे दी। फरवरी 2015 में जियोमी मोबाइल कंपनी ने आंध्रप्रदेश सरकार के साथ काम करने का प्रस्ताव रखा है। अगस्त 2015 में लेनोवो ने कहा कि उसके मोटोरोला के मोबाइल चेन्नई के पास प्लांट में निर्मित होने लग गये हैं। दिसम्बर 2015 में वीवो मोबाइल कंपनी ने नॉएडा में अपने मोबाइल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जिसमें 2200 लोगों को रोजगार मिला है। इसके साथ–साथ कई विदेशी कंपनियों ने सरकार को अपने प्रस्ताव भेजे हैं और साथ देने की इच्छा प्रकट की है।

दिसम्बर 2015 में जापान के प्रधानमंत्री ने भारत यात्रा की उन्होनें 'मेक इन इंडिया' प्रोजेक्ट के लिए जापान की ओर से भारत को 12 लाख करोड़ का फंड दिया। इसके साथ जब नरेन्द्र मोदी दिसम्बर में रूस के दौरे पर थे तब उन्होनें मेक इन इंडिया कैम्पेन के तहत अब तक की सबसे बड़ी डील साइन की। मलती रोल हेलिकॉप्टर भारत में निर्मित हैं जिन्हें रूस ने खरीदने का निश्चय किया है। 'मेक इन इंडिया' योजना से जुड़ी बातें – इस योजना ने देश विदेश के सभी स्थानों के निवेशकों के लिए भारत में व्यापार करने के दरवाजे खोल दिए हैं। बड़ी–बड़ी कंपनियां इस मंत्र को अपना रही है। भारत दुनियाँ का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो अब अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की राह पर चल पडा है।

सरकार ने इस योजना के लिए 25 सेक्टर का चुनाव किया है जैसे – ऑटोमोबाइल, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, इलेक्ट्रानिक्स, फूड प्रोसेसिंग, इन्फोर्मेशन टेक्नॉलोजी, लेदर, माइनिंग, मिडिया व एंटरटेनमेंट, आउल व गैस, रेलवे, पोर्ट्स एंड शिपिंग, टेक्सटाइल व गारमेंट्स, थर्मल पॉवर, टूरिज्म, इलेक्ट्रिकल मशीन, रोड़ व हाइवे, विमान उद्देश्य निर्माण आदि। इसके अतिरिक्त रक्षा, स्पेस और भी दूसरे सेक्टर के मार्ग यहाँ निवेश के हेतु खुल गए हैं। इसके साथ ही नियामक राजनीति ने निवेशकों व व्यापार करने वालों को बहुत सी छूट भी दी है। आंकलन के अनुसार ये पूरी योजना 20 हजार करोड़ की है लेकिन शुरूआत में इसके लिए 930 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान किया गया है, जिसमें से 50 करोड़ भारत सरकार दे रही है।

प्रत्येक देश में व्यापार व निवेश करने के अलग अलग नियम कानून होते हैं। 2015 में 189 देशों के बीच वर्ल्ड बैंक द्वारा एक रिसर्च की गई जिसके अनुसार भारत की रैंक 130 नंबर है। सरकार इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर योजनाऐं बनाती हैं। अब देश में व्यापार से संबंधित बहुत से नियम बदले जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने भारत में व्यापार के लिए देश के 17 शहरों में सर्वे किया था जिसके अनुसार लुधियाना, हैदराबाद, भुवनेश्वर, गुड़गांव, अहमदाबाद टॉप 5 शहर हैं, जहाँ आसानी से कोई व्यापार किया जा सकता है।

मेक इन इंडिया कैम्पेन

'मेक इन इंडिया' कैम्पेन को जन जन तक पहुँचाने के लिए 13 फरवरी 2016 को मुम्बई में 'मेक इन इंडिया वीक इवेंट' मनाया गया था। जहाँ 2500 अन्तर्राष्ट्रीय व 8000 राष्ट्रीय कंपनियों ने सहभागिता की थी, इसके साथ ही 72 देशों की बिजनेश टीम व देश के 17 प्रदेशों से भी उद्यमि आए थे। मेक इन इंडिया की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने मेक इन महाराष्ट्र कैम्पेन शुरू किया। इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया को और आगे बढ़ाना है। इससे महाराष्ट्र में व्यापार के लिए लोग आकर्षित होंगे व अर्थव्यवस्था सुधरेगी।

निष्कर्ष

यह कहा जा सकता है कि जब भी राष्ट्र की एकता–अखण्डता, संप्रभुता और संस्कृकति को आघात पहुंचता है तो राष्ट्रवाद का स्वतः स्फूर्त जागरण होता है। यदि वैश्वीकरण का जोर शीतयुद्ध की समाप्ति (1990), सोवियत संघ के विघटन (1991) विचारधाराओं का अंत (डेनियल बेल), इतिहास का अंत (फकियामा) तथा एक ध्रुवीय विश्व जैसी संकल्पनाओं से खादपानी ग्रहण कर विश्व को समतल बनाने का हो तब वैश्वीकरण के विरूद्ध विभिन्न राष्ट्रीयताओं का उठना एक स्वाभावितक प्रक्रिया होंगी किन्तु यदि वैश्वीकरण राज्यों के हाथ में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी देकर नागरिकों के उत्थान हेतु बल प्रदान करता है, पूंजी प्रवाह बढ़ाता है तथा विकास को बढ़ावा देता है तो निश्चित रूप से राज्यों की सीमाओं और कानूनों के शिथिल पड़ने की संभवाना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। फिर भी हमें यह नही भूलना चाहिए कि वैश्वीकरण की आड़ में 'पश्चिमीकरण' या 'द वर्ल्ड इज फ्लैट' का विचार हो अथवा राष्ट्र–राज्य व संस्कृति–रक्षा की आड़ में चरम राष्ट्रवाद का उद्भव, दोनों ही स्थितियां मानवता के लिए हानिकारक है। अतः इनके संतुलन पर जोर होना चाहिए ताकि बिग ऑयल जैसी कंपनी दूसरे देशों में कानूनी लूट न कर सके, न ही अरब स्प्रिंग जैसी घटना हो। यह बात सच है कि इतिहास की बढ़ती धारा को मोड़ा नहीं जा सकता इसलिए उसे और अधिक पारदर्शी और जन–हितैषी बनाना हमारा पुनीत कर्तव्य है। अतः भारत ने मध्य का रास्ता खोज कर 'भारत में बनाओ' कार्यक्रम आरम्भ किया है। चाहे अन्यदेश इसे 'स्वदेशी' को प्रोत्साहन कहे या राष्ट्रवादी होने का आरोप लगाये लेकिन भारत ने विदेशी निवेश को प्राथमिकता देकर इस आरोप को भी कमजोर कर दिया है। पड़ौसी देश चीन ने भी 'मेक इन चाइना' अपनाकर अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को प्राथमिकता प्रदान की है। स्पष्टतः निःसंकोच यह माना होगा कि 'मेक इन इंडिया' योजना वैश्वीकरण के युग में भारत के विकास को परवान चढ़ायेगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- मस्तरामः आलेख–विश्व–ग्राम नहीं : ग्राम विश्व बनाइए, राजस्थान पत्रिका जनवरी, 1996
- सिंह, एस. एनः राजनीति विज्ञान शब्दकोष, रावत पब्लिकेशन, जयपुर 2013
- सिंह रमेशः भारतीय अर्थव्यवस्था, मेकग्रोहिल प्रा. लि. 2019, पृ सं. 6–3

- पुरी, वी. के., मिश्र, एस. के.: भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई 2018 पृ.स. 463
- पुरी, वी. के., मिश्र, एस. के.: भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई 2018 पृ.स. 464
- महर्षि राजीवः भारत–2019, मेकग्रोहिल ऐजूकेशन–2019, पृ.स. 1–6–107
- महर्षि राजीवः भारत–2019, मेकग्रोहिल ऐजूकेशन–2019, पृ.स. 1–6–108
- जगदीश भगवतीः इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाईजेशन
- सेन, अमृतः आलेख–कैसे आंका जाए वैश्वीकरण को
- प्रदीप मल्हौत्राः आलेख–वैश्वीकरण एवं भारत
- अग्रवाल, पी. के., भट्ट, आर. के.: ग्लोबलाईजेशन, इंडिया एवं वर्ल्ड, कन्सेपर्ट पब्लिकेशन, प्रा. लि., नई दिल्ली 2011
- दुबे अभ्यास कुमार (संपा): भारत का भूमण्डलीकरण, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली 2015
- चौकसे, मनीताः आलेख–वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भारतीय समाज पर प्रभाव
- चतुर्वेदी अनूपः आलेख–वैश्वीकरण का भारतीय समाज एवं संस्कृति पर प्रभाव
- भट्टाचार्य अरविन्दमः आलेख–मेक इन इंडिया– टर्निंग विजन इन टू रियलिटी
- तलवार सौरभः आलेख–हाउ केन न्यू गर्वनमेंट मेक इंडिया ए ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब
- बिस्वाल तपनः अंतराष्ट्रीय संबंध, ओरिएन्ट ब्लैक स्वॉन प्रा. लि. नई दिल्ली 2016
- चक्रवती विद्युतः वैश्वीकृत दुनिया में लोक प्रशासन सिद्धान्त और पद्धतियां, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2018
- सिंह एस. एनः राजनीति विज्ञान शब्दकोष, रावत पब्लिकेशन, जयपुर 2013
- कटारिया, सुरेन्द्रः ग्लोबलाईजेशन इन इंडिया, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर 2018
- कटारिया, सुरेन्द्रः वैश्वीकृत भारत में जनजातीय विकास, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर 2018
- अनूप होताः भूमण्डलीकरण, बाजार और समकालीन कहानी, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर 2019
- सिंह रामगोपालः वैश्वीकरण मीडीया और समाज, नेशनल पब्लिशिंग 2014
- महर्षि राजीवः भारत–2019, मेकग्रोहिल एजूकेशन इंडिया प्रा. लि., चैन्नई 2019
- सिंह रहीसः वैश्विक संबंध, पीपासन, चंडीगढ़ 2013.

❖◆❖